



2026:AHC:178127

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8444 सन् 2026

जोगेन्द्र सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 1 अन्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

प्रार्थी हेतु अधिवक्तागण

: अजय कुमार यादव, सुधीर कुमार अग्रवाल

विपक्षी हेतु अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक-72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- (1) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- (2) वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 317 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 64(1) बी0एन0एस0, थाना चाँदपुर, जनपद बिजनौर में, उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- (3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। अभिकथित घटना दिनांक 25.5.2026 को सायं 18:00 बजे घटित होना कही गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.5.2026 को 21:36 बजे धारा 115(2), 75(2), 76, 351(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता एक विवाहित महिला है, लगभग 35 वर्ष की आयु की। पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसके बाएँ हाथ पर केवल नीलगू संस्फोट अंकित की गई थी। उस चोट के अतिरिक्त, पीड़िता के शरीर पर कोई अन्य चोट अंकित नहीं की गई। पीड़िता के शरीर से कोई आन्तरिक चोट नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पाई गई। यह भी निवेदन किया गया है कि जब पीड़िता का बयान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, तब उसने यह अभिकथित नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया, अपितु उसने कहा कि उसके साथ कोई कुकृत्य नहीं किया गया। जब पीड़िता का बयान दिनांक 30.5.2026 को धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, तब उसने यह अभिकथित किया कि प्रार्थी द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को सम्बन्धित विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 22.6.2026 के आदेश द्वारा धारा 76, 115(2), 75(2), 351(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। विवेचना अधिकारी ने अब धारा 64(1) बी0एन0एस0 जोड़ी है। प्रार्थी प्रार्थना करता है कि उसे जोड़ी गई धारा 64(1) बी0एन0एस0 में भी अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाए। प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। अब धारा 64(1) बी0एन0एस0 जोड़ी जा चुकी है, पुलिस प्रार्थी को जोड़ी गई धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

- (4) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के **भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य; 2016 (1) एस0सी0सी0 (क्रि0) 240** में प्रतिवेदित तथा **मनोज सुरेश जाधव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य; 2018 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 3428** में प्रतिवेदित निर्णयों पर विशेष निर्भरता रखी है, जिनमें उक्त मामलों में प्रार्थी को धारा 439 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नियमित जमानत पर छोड़े जाने के पश्चात्, धारा 438 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जोड़ी गई धाराओं में अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 438 दं0प्र0सं0 संख्या 9742 सन् 2021** में पारित निर्णय पर भी निर्भरता रखी है, जिसमें अभियुक्त को नियमित जमानत प्रदान किए जाने के पश्चात् अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्रार्थी विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। यह भी कथन किया गया है कि यदि प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की



स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।

(5) दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू को विवादित नहीं किया।

(6) मैंने दोनों पक्षों के प्रतिस्पर्धी निवेदनों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

(7) **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (एन0सी0टी0 दिल्ली) तथा 1 अन्य; (2020) 5 एस0सी0सी0 1** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्षियों को धमकाने सहित साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की सम्भावना, देश छोड़कर जाने जैसे न्याय से बचकर भागने की सम्भावना आदि पर विचार करना होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय, सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गम्भीरता, प्रार्थी को अधिरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारणीय बिन्दुओं से निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना अथवा न करना विवेकाधिकार का विषय है।

(8) **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य; (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 676** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो जाए अथवा यह एक जघन्य अपराध हो अथवा जहाँ साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी विधिसम्मत होने के कारण की जा सकती है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व एवं उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य भेद किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्म-सम्मान को अपरिमेय क्षति पहुँचा सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवज्ञा करेगा तथा वस्तुतः उसने पूरे समय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

(9) अग्रिम जमानत से सम्बन्धित सुस्थापित विधिक सिद्धान्त, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों, अभियोग की प्रकृति, प्रार्थी की भूमिका तथा मामले की समस्त सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत हेतु मामला बनता है।

(10) तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निदेशों के साथ अनुमत किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित प्रार्थी-जोगेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाएगा, इस शर्त पर कि वह सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी अथवा सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए रु0 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करे।

(ii) प्रार्थी विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किए जाने पर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रखने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा

(iv) प्रार्थी न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(11) उपर्युक्त शर्तों में से किसी की चूक अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, प्रार्थी को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 24 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।